Anganwadi workers and helpers working at Anganwadi Centres are honorary and part-time (4½ hours a day) voluntary workers selected from local community. They cannot be treated as Government employees or given minimum wages as it will be contrary to the concept of community involvement which is the basis of the Integrated Child Development Services Programme. They are given fixed honorarium that has been enhanced from time to time. The matter regarding revision of honorarium of Anganwadi workers and helpers is, however, getting Government's utmost attention. Instructions have been issued to the State Government/U.T. Administrations that they may consider suitable recruitment rules wherein qualified Anganwadi workers can be considered for appointment as Supervisors.

गुजरात में अनधिकृत खुदाई

1692. **श्री राजूभाई ए० परमार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में अनेक स्थानों पर खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को मूर्तियां और ऐतिहासिक महत्व की विभिन्न प्राचीन वस्तुएं मिली थीं;

(ख) क्या उक्त विभाग ने आगे खुदाई का कार्य रोक दिया है और उस इलाके में अनधिकृत खुदाई का कार्य हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार उस क्षेत्र में खुदाई का कार्य पुनः शुरू करने और अनधीकृत खुदाई को रोकने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री, (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने धोलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात में उत्खनन-कार्य किया है जिससे प्रकाश में निम्न वस्तुए आई:-विभिन्न मिट्टी के बर्तनों के अलावा, चहारदीवारी वाली हड़प्पा काल की बस्ती एवं पूर्ववर्ती वस्तुए, संरचनात्मक अवशेष, एक शिलालेख, मोहरें मुद्रांकनें, पकी मिट्टी की लघु मूर्तियां, शख, ताम्बे एवं पत्थर की पुरा-वस्तुएं ।

(ख से (ङ) इस स्थल पर कोई अनधिकृत उत्खनन-कार्य नहीं किया गया है । तथापि, इस स्थल पर उत्खनन-कार्य का पुनरारम्भ 'पुरातत्व की केन्द्रीय सलाहकार समिति की स्थायी समिति द्वारा सामग्री' आदि' की छानबीन किए जाने और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर करता है ।

ग्रामीण शिक्षा के लिए आवंटन

1693. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण शिक्षा के लिए अपर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है जबकि बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण शिक्षा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) प्राइमरी, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रदत्त सरकारी सहायता, जो 1992-93 की वार्षिक योजना में शिक्षा पर कुल केन्द्रीय परिव्यय का 64.39! है, के लाभ मुख्यतः ग्रामीण

क्षेत्रों को मिलते हैं । केन्द्रीय सरकार आपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षा शिक्षक, व्यावसायिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय और प्रौढ़ साक्षरता जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है ।

विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता का विवरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1991–92, भाग–I में दिया गया है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है ।

Misappropriation of Funds

1694. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 4132 given in the Rajya Sabha on 27th March, 1992 and state:

(a) whether any official involved in the misappropriation case has since been identified;

(b) if so, the action taken against the official;

(c) whether Government propose to oredr a thorough enquiry into all projects|schemes handled by the said official to unearth such misappropriation of funds; and

(d) whether Government propose to instruct the authorities not to hand over project|schemes involving use of Government funds to the said official to avoid misappropriation of funds in future?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) As already stated in reply to Question No. 4132 answered in Rajya Sabha on 27-3-1992, no official has been entrusted with any project, but the work of data entry of the project, 'People of India', has been entrusted to National Informatic Centre. A case of misappropriation with regard to payment made to one data entry operator, it is ascertained, had come to light. The amount involved is Rs. 3450|-. It is ascertained that the case has been entrusted to the Central Bureau of Investigation.

Rehabilitation of Vagrant Children

1695. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of WELFARE: be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increasing member of vagrant and abandoned children all over the country;

(b) what steps Government propose to take to start a social welfare programme to attend to this problem;

(c) whether UNICEF has financed any specific schemes for this section of children; and

(d) whether there are any programmes under implementation with UNICEF assistance for the rehabilitation of the vagrant and abandoned children?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes,

(b) During the Eighth Five Year Plan, the Government propose to start a new Central Scheme for the welfare of Street Children which will also take care of the category of children mentioned above. The scheme envisages to provide welfare services such as nutrition, health, non-formal education, vocational training to Street Children. The Scheme will be implemented through voluntary organisations.

(c) and (d) The Government has formulated a City-Level Programme